मान्यवर, गेहूं के मामले में थोड़ा नमी भी देखी जाती है कि यह नमी 12 प्रतिशत होनी चाहिए। ऐसे हमारे मानक हैं, लेकिन जो आस्ट्रेलिया से गेहूं आ रहा है, उसमें नमी 13.5 प्रतिशत की है। इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा पिछली बार हमने देखा कि एक सफेद फूल का घास आ गया और उसके कारण आज हालत यह है कि किसान को एलर्जी होती है, फसल होती नहीं। इन शंकाओं को निर्मूल नहीं बताया जाता कि आस्ट्रेलिया से जो गेहूं आया है, इसमें ऐसे ही खतरनाक खर-पतवार के बीज भी निश्चित रूप से आए होंगे। प्रेस के जरिए से हमको यह जानकारी मिली है कि उसमें कुछ ऐसे खर-पतवार आए हैं, जिनसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब किसान को खाद पर सबसिडी देने की बात आती है, तो बार बार हमारा प्लानिंग कमीशन और दूसरे लोग यह कहते हैं कि खाद पर सबसिडी कम करो, किसान को सबसिडी कम करो, बिजली उसको सस्ते दाम पर मत दो, लेकिन आस्ट्रेलिया के किसान को 3000/-रुपए प्रति मी0टन ज्यादा देकर उसके लिए आस्ट्रेलिया से वाहवाही लूट लो। यह विरोधाभास का मामला है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में कम से कम इतना तो आप करें कि एक तो सिंचाई के लिए व्यवस्था हो, जिससे हमारा सिंचित क्षेत्र बने, जो हमारी निष्प्रयोग भूमि पड़ी है, जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, उसको सुधार करके उसको खेती करने के योग्य बनाने के लिए खर्च किया जाए और किसान को सस्ती दर पर बिजली देने का काम कराया जाए, ताकि किसान ज्यादा उत्पादन कर सके। फिर उसका उत्पादन सही दाम पर बिक सके, इसके लिए आप नेफेड को सक्रिय कीजिए।

मान्यवर, मंडी समिति की हालत भी ऐसी है, हालांकि यह प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है, परन्तु प्रभाव आपका है। आपके जो सेंट्रल वेयरहाऊस हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, जहां धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, वहां आपके वेयरहाऊस नहीं हैं। आपके वेयरहाऊस शहरों में, कस्बों के पास मिलेंगे, कहीं जंगल या खेत के आसपास की सड़कों पर नहीं हैं। आज आवश्यकता है कि वेयरहाऊस नजदीक बनवाएं, ताकि किसान को अपनी फसल रखने की ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इस बार तो ऐसी शंका हुई है कि आपके किसान के गेहूं की फसल कम नहीं हुई है, उस गेहूं को बिचौलियों ने खरीद लिया और उसे अपने माल-गोदाम में रखकर उससे गरीब और किसान, दोनों को लूटने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ओर ध्यान देने का काम करें और किसान के आंसू पोंछने का काम भी करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before the hon. Minister replies, there are statements to be made by the Ministers.

STATEMENT BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations contained in the Einghty-First and Eighty-Sixth Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture and

Status of implementation of recommendations contained in the Eighty-Second and Eighty-Fourth Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): Sir, I lay a copy each of the statements.

Status of implementation of recommendations contained in the Eighteenth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI M.V. RAJASEKHARAN): Sir, I lay a copy of the statement.

SHORT DURATION DISCUSSION

Import of wheat and agrarian distress *-Contd.*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): उपसभापति महोदय, देश के सामने आजकल एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है, इस समस्या के बारे में राजनीति को दूर रखकर कोई कदम उठाने की आवश्यकता है और किस तरह से हम कदम उठा सकते हैं, इस बारे में अच्छे सुझाव सदस्यों ने यहां दिए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश के किसानों के सामने आत्महत्या जैसी परिस्थिति पैदा हो रही है। वैसे कहें तो यह परिस्थिति आज की नहीं है, मगर यह स्थिति इस देश में रहने वाले आप, हम, सभी के लिए एक तरह की चिंता पैदा करने वाली है।

यह बात सच है कि एक जमाने में भारत खाद्यान्न इम्पोर्ट करने वाला देश था, लेकिन पिछले कई सालों में देश की फूड सिक्युरिटी की समस्या हल करने के लिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इस देश को कामयाबी मिली, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश के किसानों को दिया जाना चाहिए और देशवासियों ने उनको श्रेय दिया भी है। इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने जो पिछले कई सालों में काम किया - नया रास्ता दिखाया, नए बीज पैदा किए, नई टैक्नोलॉजी पैदा की, इसका भी असर देश के कृषि उत्पादन पर अच्छा हुआ, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मगर, पिछले कई सालों से जो एक राष्ट्रीय उत्पादन की आवश्यकता थी, ग्रोथ रेट की आवश्यकता थी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, मगर इस साल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे यह बात साबित हुई कि हमारा ग्रोथ रेट 4 परसैंट होने की आवश्यकता थी और जो टारगेट हम लोगों ने तय किया था, उस टारगेट के आसपास हम लोग इस साल पहुच रहे हैं। एक तरफ इस टारगेट के आसपास हम पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कई फसलों के बारे मे हमारा उत्पादन भी ठीक है और तीसरी तरफ हम यह परिस्थिति देख रहे हैं कि आत्महत्याओं की स्थिति में लगातार पिछले कई वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया है।

गेहूं के आंयात की परिस्थिति भी आज इस देश के सामने और इस सरकार के सामने आई है। आत्महत्या के बारे में इससे पहले इस सदन में दो बार बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था